

राजपत्र

tte ot Indi

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 239〕 No. 239〕 नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2001/वैशाख 26, 1923 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2001/VAISAKHA 26, 1923

> वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अधिसूचना नई दिल्ली, 16 मई, 2001 सं. 28/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 359( अ). — केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिंकतयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 82/92-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 अगस्त, 1992 [सा. का. नि. 744(अ), तारीख 27 अगस्त, 1992] को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, ऐसे सभी उत्पाद शुल्क्य मालों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को जिन्हें सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में या मुक्त व्यापार जोन में या विशेष आधिक जोन में उत्पादित या विनिर्मित किया गया है और जिनकी निकासी ऐसे व्यक्ति को को गई है जो—

- (क) प्रक्रियाओं के हस्तक के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित, निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.7 के निबंधनों में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अग्निम अनुज्ञप्त के विरूद्ध जारी अग्निम निर्मुक्ति आदेश को या प्रक्रियाओं के हस्तक के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित, निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.8 के निबंधनों में किसी बैंक द्वारा जारी बैंक-टू-बैंक अन्तर्देशीय साखपत्र को धारण कर रहा है, उस पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है;
- (ख) प्रक्रियाओं के हस्तक के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित, निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.7 के निबंधनों में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा शुल्क मुक्त पुन:पूर्ति प्रमाण-पत्र (डी एफ आर सी) के विरूद्ध जारी अग्रिम निर्मुक्ति आदेश को या प्रक्रियाओं के हस्तक के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित, निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.8 के निबंधनों में किसी बैंक द्वारा जारी बैंक-टू-बैंक अन्तर्देशीय साखपत्र को धारण कर रहा है, उस पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग से, जो भारत से बाहर उत्पादित या विनिर्मित समान मालों पर, यदि उनका भारत में आयात किया जाता है तो, उद्ग्रहणीय ऐसे सीमाशुल्क के जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिच्च है, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम को धारा 3क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के समतुल्य है, छूट प्रदान करती है; किन्तु यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात :---
  - (i) अग्रिम अनुज्ञिष्त धारक/डी एफ सी आर सी धारक, केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष यथास्थित, उक्त अग्रिम निर्मृक्ति आदेश उसमें इस अधिसूचना के अनुसार निकासी किए जाने के लिए अनुज्ञात उक्त मालों में से प्रत्येक की मात्रा, वर्णन (इसमें तकनीकी विनिर्देश भी सिम्मिलित हैं) और मूल्य विनिर्दिष्ट करते हुए या उसके बैक-टू- बैक अन्तर्देशीय साखपत्र की प्रति उसमें मूलत: देसी प्रदायकर्ता का नाम और पता विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करता है, और

- (ii) उक्त भाल की निकासी अनुज्ञात करने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, उक्त अग्निम निर्मृक्ति आदेश या बैक-टू-बैक अन्तर्देशीय साखपत्र में प्रत्येक मद की मात्रा और मूल्य घटा दिए जाते हैं। स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—
  - (i) ''निर्मात और आयात नीति'' से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 1/1997-2002 तारीख 31 मार्च, 1997 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 अभिप्रेत हैं;
  - (11) "प्रत्येक प्रक्रियाओं के इस्तक" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की समय-समय पर मथा संशोधित सार्वजियक सूचना सं. 1 (आई ई-2001)/1997—2002, तारीख 31 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित प्रक्रियाओं का हस्तक वोल्यूम 1, 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 अभिप्रेत है;
  - (iii) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है।

[फा. सं. 305/53/2001 एफ टी टी] राजेन्द्र सिंह, अवर सिंधव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2001 No. 28/2001-Central Excise

G.S.R. 359 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India In the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.82/92-CE, dated the 27<sup>th</sup> August, 1992 [GSR 744(E), dated the 27<sup>th</sup> August, 1992], the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all excisable goods (hereinafter referred to as the said goods) specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), produced or manufactured in a hundred per cent export oriented undertaking or a free trade zone or a special economic zone and cleared to a person -

- (a) holding an advance release order issued by the licensing authority against an advance licence in terms of paragraph 7.7 of the Export & Import Policy, read with relevant provisions of the Handbook of Procedures, or a back to back inland letter of credit issued by a bank in terms of paragraph 7.8 of the Export and Import Policy read with relevant provisions of the Handbook of Procedures from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excise Act;
- (b) holding an advance release order issued by the licensing authority against a Duty Free Replenishment Certificate (DFRC) in terms of paragraph 7.7 of the Export & Import Policy read with relevant

provision of the Handbook of Procedures or a back to back inland letter of credit issued by a bank in terms of paragraph 7.8 of the Export and Import Policy read with relevant provisions of the Handbook of Procedures from that portion of duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Central Excise Act, as is equal to the duty of customs leviable on like goods produced or manufactured outside India if imported into India, which is specified in the First Schedule to the Custom Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and special additional duty of customs leviable thereon under section 3A of the said Customs Tariff Act:

# subject to the following conditions, namely:-

- (i) the advance licence holder/ DFRC holder produces the said advance release order specifying therein the quantity, description (including the technical specifications) and the value of each of the said goods permitted to be cleared in accordance with this notification or, as the case may be, his copy of back to back inland letter of credit specifying therein the name and address of the indigenous supplier in original before the proper officer of Central Excise/Customs; and
- (ii) the quantity and the value of each of the items are debited by the proper officer of Central Excise/Customs in the said advance release order or as the case may be, the back to back inland letter of credit, before allowing clearance of the said goods.

# Explanation. - For the purposes of this notification, -

- "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy, 1<sup>st</sup> April, 1997-31<sup>st</sup> March, 2002, published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No.1/1997-2002, dated 31<sup>st</sup> March, 1997, as amended from time to time;
- (ii) "Handbook of Procedures," means the Handbook of Procedures, Vol.I, 1st April, 1997-31st March, 2002, published vide Public notice of the Government of Indla in the Ministry of Commerce, No. 1(RE-2001)/1997-2002, dated the 31st March 2001, as amended from time to time;
- "Licensing Authority," means an authority competent to grant a licence under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or the rules made thereunder.

# अधिसूचना

## नई दिल्ली, 16 मई, 2001

# सं. 55/2001-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 360( अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए यह समाधन हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत आने वाले तरासे हुए और पालिश्कृत हीरे जब उनका भारत में निर्यात और आयात नीति के पैरा 8.13(अ) के निबंधनों के अनुसार, शर्त (iv) में वर्णित प्रयोगशालाओं/अधिकरणों द्वारा प्रमाणन/श्रेणीकरण के पश्चात् आयात किया जाता है, उन पर उदग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उदग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात् :—

- (1) तरासे हुए और पालिशकृत हीरों का ऐसे रत्न और आभूषण निर्यातकर्ताओं द्वारा पुन: आयात किया जाता है। जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का ट्रेक रिकार्ड है और जिनके पास पूर्ववर्ती तीन अनुज्ञापन वर्षों के दौरान पांच करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत आवर्ष है।
- (11) इस प्रकार पुनः आयातित तरासे हुए तथा पालिशकृत हीरों के प्रत्येक भाग भार में एक कैरट का 0.50 से कम नहीं होगा।
- (111) तरासे गए तथा पालिशकृत हींर निर्यात की तारीख से तीन मास की अविध के भीतर पुन: आयातित किए जाएंगे।
- (IV) तरासे गए तथा पालिशकृत हीरों को , उक्त पैरा 8.13(ख) के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित प्रयोगशालाओं/अभिकरणों से प्रमाणन/श्रेणीकरण की रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर ही पुनः आयात किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा; अर्थात् :—
  - (क) जेमोलोजिकल इन्सटीटयूट आफ अमेरीका (जी आई ए);
  - (ख) राबर्ट मोउआवाड कैम्पस;
  - (ग) इन्टर नेशनल जेमोलोजिकल इन्सटीट्यूट (आई जी आई);
  - (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय जेमोलोजिकल लेबोरेटरी (ई जी एल), और
  - (ड) होज राड वुअर डायमंड (एच आर डी) आन्टवरप, बेल्जियम, और
  - (च) वर्ल्ड डायमङ सेन्टर आफ डायमंडस हाई काउंसिल, आन्टवरप, बेल्जियम
- (v) इस प्रकार पुनः आयातित तरासे गए और पालिशकृत हीरे मूल्य, ऊँचाई, परिधि और भार के निबंधनों के अनुसार निर्यात के समय बीजक में उल्लिखित तत्समान हीरों के सदृश होंगे।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ''निर्यात और आयात नीति से, भारत सरकार के वाणिण्य मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना मं. 1/1997-2002 तारीख 31 मार्च, 1997 द्वारा प्रकाशित'' निर्यात और आयात नीति; 1 अप्रैल, 1997— 31 मार्च, 2002 अभिप्रेत हैं।

> [फा. सं. 305/53/2001 एफ टी टी] राजेन्द्र सिंह, अबर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2001

#### No. 55/2001-Customs

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cut and polished diamonds falling within Chapter 71 of the First Schedule to the Customs Tariff Act,

1975 (51 of 1975), when re-imported into India after certification/ grading by the laboratories / agencies mentioned in condition (iv), in terms of paragraph 8.13(b) of the Export & Import Policy, from the whole of duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

- (i) Cut and pollshed diamonds are re-imported by gems and jewellery exporters having a track record of at least three years and having an annual average turnover of five crore rupees and above during the preceding three licensing years.
- (ii) Each piece of cut & polished diamonds so re-imported shall not be less than 0.50 of a carat in weight.
- (iii) Cut and polished diamonds shall be re-imported within a period of three months from the date of exportation.
- (iv) Cut and polished diamonds shall be allowed to be re-imported only on production of certification/grading report from the following laboratories/ agencies, in terms of said paragraph 8.13(b), namely:-
  - (a) Gemological Institute of America (GIA);
  - (b) The Robert Mouawad Campus;
  - (c) International Gemological Institute (IGI);
  - (d) European Gemological Laboratory( EGL) In USA;
  - (e) Hoge Raad voor Diamond (HRD), Antwerp, Belglum; and
  - (f) World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium.
- (v) Cut and polished diamonds so re-imported shall match with corresponding diamonds mentioned in the invoice at the time of exportation in terms of value, height, circumference and weight.

**Explanation**.- For the purposes of this notification, "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy, 1<sup>st</sup>, April, 1997-31<sup>st</sup> March, 2002, published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No.1/1997-2002, dated 31<sup>st</sup> March, 1997, as amended from time to time.

[F. No. 305/53/2001-FTT] RAJENDRA SINGH, Under Secy.